बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 4

11 फाल्गुन, 1938 (श.)
वृहस्पतिवार, तिथि ---------------------------------
02 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 24

1.	वाणिज्यकर विभाग	....	....	01
2.	समाज कल्याण विभाग	....	....	04
3.	जल संसाधन विभाग	....	....	06
4.	योजना एवं विकास विभाग	....	....	01
5.	परिवहन विभाग	....	....	02
6.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	04
7.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	02
8.	वित्त विभाग	....	....	01
9.	पर्यावरण एवं वन विभाग	....	....	01
10.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	01
11.	अनु. जाति/जनजाति कल्याण विभाग	....	....	01
			कुल योग –	**24**

राजस्व की क्षति

*** 56. श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, वाणिज्यकर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चकिया में कृष्णा कंक्रीट इंटरप्राइजेज तथा आकाश कंस्ट्रक्शन के नाम पर पिछले 5 वर्षों से गिट्टी की रैक प्रति रैक 5 हजार मैट्रिक टन से भी ज्यादा गिट्टी मंगाई गयी है जिसमें बिना सेल्स टैक्स चुकाये इसको बेचा गया तथा वाणिज्यकर विभाग, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) को करोड़ों रुपये के टैक्स का नुकसान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि करोड़ों रुपये की सेल्स टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है, जाली पेपर का इस्तेमाल कर झारखंड के बड़हरवा समेत अन्य जगहों से पांच साल के अन्दर गिट्टी का रैक चकिया में लगाकर रेल थाना, वाणिज्यकर एवं अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व की लूट की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया में गिट्टी का रैक झारखंड के विभिन्न स्थानों से लाखों लाख मैट्रिक टन कृष्णा कंक्रीट इंटरप्राइजेज एवं आकाश कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर एवं पुलिस विभाग एवं वाणिज्यकर की मिलीभगत से किये गये करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व की क्षति की भरपाई कराने के साथ उक्त लोगों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

लंबित राशि का भुगतान

*** 57. श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 तक मधुबनी जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के पेंशनार्थियों की राशि आवंटित कर दी है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के कथनानुसार माह फरवरी, 2016 तक पेंशनार्थियों की राशि संबंधित विभाग को आवंटित कर दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि माह मार्च से सितम्बर, 2016 तक की राशि पेंशनार्थियों के खाता के माध्यम से आवंटित कर दी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत पंचायत के पेंशनार्थियों को 18 माह से पेंशन की राशि नहीं मिलने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति बन गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मधुबनी जिला के पेंशनार्थियों को लंबित राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बांध का निर्माण

* 58. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत नारायणपुर पंचायत के ग्राम-बागपुर में मनीसुंगरा एवं बरना पहाड़ों के बीच मनी नाला पर बांध नहीं रहने से दर्जनों गांव के किसानों को खेती में पानी नहीं पहुंच पा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु मनी नाला पर मनीसुंगरा एवं बरना पहाड़ के बीच बांध का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

रोजगार के अवसर से वंचित

* 59. **श्री मंगल पाण्डेय**: क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत बिहार में 3500 केन्द्रों को खोलकर एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्रों में युवाओं को भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी) संवाद कौशल, क्म्प्यूटर भी दिया है, 240 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया परन्तु पदाधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही के कारण कार्यक्रम से लाभार्थी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर से वंचित होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इतनी महत्वपूर्ण योजना को शीघ्र लागू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पुल का निर्माण

* 60. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत कुचायकोट प्रखंडाधीन बनतैल पंचायत के मठिया गांव के नजदीक सारण मुख्य नहर पर अवस्थित मात्र चार फीट चौड़ा पुल ध्वस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल के ध्वस्त होने से आम ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में कबतक उक्त पुल का निर्माण करना चाहती है?

नावों का अवैध परिचालन

* 61. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के खतरनाक नदी घाटों पर नावों का परिचालन हो रहा है, दलदल में नाव परिचालन की कोई सुविधा नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि पूरे राज्य मे करीब 600 खतरनाक घाट हैं सिर्फ पटना में 31 खतरनाक घाट हैं;

(ग) क्या यह सही है कि 15 से 30 यात्रियों को ढोने वाली नावों में दो नाविक, 30 से अधिक यात्रियों को ढोने वाली नावों में तीन नाविक होने चाहिए;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खतरनाक नदी घाटों से हो रहे नावों के अवैध परिचालन पर रोक लगाते हुए खतरनाक घाटों को सुरक्षित घाट में परिवर्तित करना चाहती है, इसपर सरकार की क्या योजना है, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 62. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रजौली प्रखंड के टेकुआ टांड कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना विगत चार वर्षों से अधूरी पड़ी है;

(ख) क्या यह सही है कि इस घेराबंदी को पूरा कराने हेतु स्थानीय ग्रामीण कई बार लिखित रूप में जिलाधिकारी को अवगत करा चुके हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त टेकुआ टांड कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

लंबित मामलों का निष्पादन

* 63. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 23.01.17 को दरभंगा परिक्षेत्र के आईजी ने मधुबनी पुलिस मुख्यालय में निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि यथाशीघ्र थानों में लंबित मामलों में अनुसंधान पूरा कर आवश्यक कार्रवाई की जाय;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि दरभंगा परिक्षेत्र में लंबित मामलों पर क्या कार्रवाई की जा रही है तथा सरकार एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर लंबित मामलों का निष्पादन करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जांच-प्रतिवेदन

* 64. **श्री चंदेश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 5481/गो. दिनांक 17.12.2011 द्वारा प्रेस एवं फार्म्स, गया के उपाधीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का जांच प्रतिवेदन प्रधान सचिव, वित्त विभाग (प्रेस), बिहार, पटना को दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय वित्त मंत्री के पत्रांक 1221, दिनांक 23.11.2016 द्वारा 8 (आठ) पत्रों में उठाये विन्दुओं पर सम्यक् कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना से अपेक्षा की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधि के पत्रांक वि.प.आ. क्रिया. 60, दिनांक 23.12.2016 द्वारा उक्त उपाधीक्षक, प्रेस एवं फार्म्स, गया के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के जांच प्रतिवेदन पर आवश्यक/विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से अवगत कराने हेतु प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि उपाधीक्षक, प्रेस एवं फार्म्स, गया पर लगाये गए आरोपों की जांच प्रतिवेदन में अंकित 68085.55 रुपये का गबन, अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन नहीं करना, प्रेस के कार्यों में अभिरुचि नहीं लिया जाना, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया के साथ असहयोगात्मक रवैया अपनाया जाना, कई वर्षों से प्रेस एवं फार्म्स, गया के उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित रहना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दमन चक्र चलाना आदि रहने पर भी अभी तक किस परिस्थिति में कार्रवाई नहीं की गई?

शहर को हरा-भरा बनाने पर विचार

* 65. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की राजधानी पटना में ओवरब्रिज एवं बाइपास सड़कों को बनाने एवं चौड़ीकरण के क्रम में सड़कों के किनारे लगे पेड़-पौधों को काट दिया गया है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़कों के किनारे-किनारे लगे पेड़-पौधों को काट देने एवं ओवरब्रिज तथा बाइपास बनाने के बावजूद नये पौधे नहीं लगाये जा सके हैं, जिससे पर्यावरण की समस्या बने रहने के आसार हैं तथा शहर की रौनक घट गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहर को हरा-भरा बनाने एवं सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से सड़कों के किनारे पौधारोपण प्रारंभ करने एवं इसके संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुशासनिक कार्रवाई

* 66. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा गया जिला के महकार में आईटीआई कॉलेज का निर्माण कराया गया है, जिसका एकरारनामा संख्या-45, एसबीडी 2015/16, दिनांक 30.06.15 है;

(ख) क्या यह सही है कि एकरारनामा के आलोक में संवेदक के द्वारा भवन का निर्माण कर लिया गया है, लेकिन वर्तमान प्राचार्य के द्वारा विगत चार माह से निजी भवन में किराया पर चलाया जा रहा है तथा मकान मालिक से रिश्वत लेकर प्राचार्य के द्वारा कॉलेज को सरकारी भवन में स्थापित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार प्राचार्य पर अनुशासनिक कार्रवाई कर कॉलेज को सरकारी भवन में स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

थाना गांव में ही कबतक

* 67. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत कोचेगा, दरभंगा ग्राम में वर्ष 1983 में नक्सलियों के द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घटना के बाद वहां पुलिस पिकेट दिया गया था, जिसे हटा लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव में नक्सलियों के द्वारा वर्ष 2001 में एक व्यक्ति की हत्या एवं वर्ष 2010 में नौ घरों की कुर्की-जब्ती कर घरों में विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया;

(घ) क्या यह सही है कि गांव से थाने की दूरी 7 किमी है जिसकी वजह से उक्त गांव नक्सलियों के निशाने पर है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गांव में पुलिस थाना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियमों का उल्लंघन

* 68. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में निजी बसों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को भीतर और बाहर छतों पर बैठाकर बसों को संचालित किया जाता है, जिससे आये दिन हादसे होते रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि निजी बसों में अधिकांश के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कोई समुचित कार्रवाई भी नहीं कर पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार जनहित में यातायात नियमों के अनुपालन हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

शिल्ट हटाने की व्यवस्था

* 69. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत पश्चिमी कोशी नहर के कमला नदी के कमला संरचना आर.डी. से आर.डी. ग्यारह सौ तीस तक उग्रनाथ उपशाखा नहर शिल्ट से भरा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उपशाखा उग्रनाथ नहर से खजौली, राजनगर, पंडौल एवं झंझारपुर प्रखंड की अठारह हजार एकड़ भूमि से अधिक की सिंचाई हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उपशाखा उग्रनाथ नहर में शिल्ट भर जाने से किसानों की सिंचाई बाधित होने के कगार पर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जून, 2017 से पहले शिल्ट हटाने की व्यवस्था कर किसानों को सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, यदि हां तो कब, नहीं तो क्यों ?

पूर्ण व्यवस्था नहीं

*** 70. श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में नेत्रहीन बच्चों के लिए कुल तीन आवासीय विद्यालय पटना, भागलपुर और दरभंगा में हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था विद्यालय की स्थिति एवं शिक्षकों का व्यापक रूप से अभाव होने के कारण इनका भविष्य अधर में है;

(ग) क्या यह सही है कि नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने हेतु ब्रेल लिपि की किताबें उक्त तीनों विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण छात्रों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि शिक्षक के अभाव के कारण नेत्रहीन छात्रों को ना ही पूर्णत: शिक्षित करना संभव हो पा रहा है और ना ही कम्प्यूटर का ज्ञान देना;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नेत्रहीन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी शिक्षा संबंधी पूर्ण व्यवस्था कराने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

त्वरित निष्पादन की व्यवस्था

*** 71. श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है राज्य मानवाधिकार आयोग में मामले की सुनवाई की गति धीमी पड़ गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि पहले से 10000 से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहीं रोजाना 30 से 40 शिकायतें राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आयोग में मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया आयोग में सदस्यों की कमी के कारण बाधित है;

(ध) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आयोग के सदस्यों के खाली पड़े पदों को भरने एवं मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नदी के तल की सफाई

* 72. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत पड़ने वाली तेल नदी एवं नून नदी के तल की ऊंचाई बढ़ने के कारण हर वर्ष बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी के तल की सफाई आजादी के बाद से आज तक नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड (क) में वर्णित नदी के तल की सफाई कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चौड़ीकरण तथा मरम्मती

* 73. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या सरकार सीतामढ़ी शहर में जाम की समस्या को देखते हुए रिंग बांध की सड़क को पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरण करते हुए उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

* 74. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालयों में सृजित पद के अनुरूप शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं तथा शिक्षकों का घोर अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालयों में रिक्त शिक्षक के पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों से भरने की योजना सरकार की है;

(ग) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् कार्य करने की इच्छा-शक्ति (क्षमता) कम हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालयों में सृजित पद के अनुरूप योग्य शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन देकर स्थायी तौर पर करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रेलयात्रा की भी सुविधा

* 75. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के तहत सेनानियों को पेंशन दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में अभी तक कितने सेनानियों को जे.पी. सेनानी सम्मान दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राज्यान्तर्गत नि:शुल्क बस यात्रा करने की व्यवस्था है, साथ ही क्या उनको इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पास निर्गत किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि जे.पी. सेनानियों एवं उनके पति/पत्नी के लिए चिकित्सा की सुविधा है, वे वर्ष में कितनी राशि का इलाज करा सकते हैं, उनके इलाज खर्च की राशि कहां से भुगतान होगी, सेनानियों के मृत्युपरांत उनके पति/पत्नी (स्पाउज) को भी उसी दर पर पेंशन एवं अन्य सुविधा देय है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो राज्य जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के अन्तर्गत पेंशनधारियों को वर्ष में कितनी बार रेल यात्रा करने की सुविधा देने का विचार रखती है?

उठाव क्यों नहीं

* 76. **श्री रणविजय कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आईसीडीएस योजना के खाद्यान्न का अक्टूबर एवं नवंबर का उठाव नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि सूबे में खाद्यान्न का उठाव हर महीने की 22 तारीख को सरकार ने तय कर रखा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि भोजपुर जिला में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खाद्यान्न नहीं उठाने का क्या कारण है?

अपहरणकर्त्ताओं के चंगुल से आजादी

* 77. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिले के राजगीर थाना में शशिभूषण कुमार, महेन्द्र भवन, राजगीर द्वारा कांड सं.-09/17, दिनांक 13.01.17 दर्ज कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री कुमार के दोनों पुत्र का दिनांक 11 जनवरी को अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिनका आज तक सुराग नहीं मिल पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि आज तक पुलिस मूकदर्शक बनी बैठी है जिसके कारण अपहृत बच्चे के माता-पिता सदमें में हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'ख' में वर्णित दोनों बच्चों को अपहरणकर्त्ताओं के चंगुल से छुड़ाना चाहती है और इस कार्य में देरी करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

धरातल पर कबतक

* 78. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव में गंगा पंप नहर योजना का निर्माण 1980 में शुरू हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के निर्माण में विभाग द्वारा करोड़ों रुपये व्यय किया गया, परंतु यह योजना आज तक धरातल पर चालू नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि इस योजना में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त योजना के चालू हो जाने पर लगभग 200 एकड़ किसानों की जमीन की सिंचाई होगी;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित योजना को किसानों के हित में धरातल पर उतारना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्यों की जांच

* 79. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि कुसुम कुमारी नियमित महिला पर्यवेक्षिका सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखंड में विगत दस वर्षों से बाल विकास परियोजना में पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उनके द्वारा बाल विकास परियोजना अन्तर्गत एवं अन्य परियोजनाओं में काफी अनियमितता एवं गड़बड़ियां की गई हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उनके कार्यकाल में की गई कार्यों की जांच एवं नियमानुकूल स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पटना
दिनांक 02 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्